हल्द्वानी (नैनीताल) एवं देहरादून से एक साथ प्रकाशित

समाचारों को विस्तार से व तत्काल पढ़ने के लिए क्लिक करें
Web:- www.jokhimnews.com
सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में "A" श्रेणी में सूचीबद्ध

जोखिम

भय भूख एवम् भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत् निर्भीक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

वर्ष : 16 अंक : 79 | हल्द्वानी (नैनीताल) शुक्रवार 30 जनवरी 2026 | मूल्य रू 2 | पृष्ठ : 8

जनपद को नशामुक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा अभियान

हल्द्वानी संवाददाता. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टी.सी. के नेतृत्व में जनपद को नशामुक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा अभियान लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। नशा तस्करी और अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि युवाओं को नशे के मकड़जाल से बचाया जा सके।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक बनभूलपुरा दिनेश सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है।पुलिस टीम द्वारा हिमालय स्कूल के पीछे, गौला बाईपास रोड, यात्री विश्राम गृह के पास चेकिंग के दौरान एक युवक को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से कुल 20 अदद नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए।पुलिस ने मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना बनभूलपुरा में मु0अ0सं0 19/26 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।गिरफ्तार अभियुक्तसमीर उर्फ बूची, पुत्र खालिद खननिवासी ख्र इन्द्रानगर, थाना बनभूलपुरा, जनपद नैनीतालउम्र 20 वर्ष बरामद नशीले इंजेक्शन Buprenorphine Injection IP 2ml – 15 vnn Pheniramire Maleate Injection (Avil) – 05 vnn

कुल . 20 अदद नशीले इंजेक्शन

पुलिस टीम में शामिल अधिकारी/कर्मचारी उ0नि0 मनोज यादव

का0 दिलशाद अहमद

का0 लक्ष्मण राम

भाजपा संगठन में मनीष यादव को मिली नई जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

डोईवाला संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा मनीष यादव को प्रकोष्ठ विभाग का ऋषिकेश जिला सह-संयोजक नियुक्त किया गया है। मनीष यादव भाजपा के समस्त प्रकोष्ठों के जिला सह-संयोजक के रूप में संगठनात्मक दायित्व निभाएंगे। उनकी नियुक्ति से क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का माहौल है।मनीष यादव भाजपा के एक कर्मठ, जमीनी और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। मनीष पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं तथा भाजपा भानियावाला में शक्ति केंद्र प्रभारी के रूप में संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।इसके साथ ही मनीष यादव हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व भी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। सामाजिक एवं धार्मिक

गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहते हुए महंत राजू दास महाराज जी के निकट सहयोगी के रूप में भी जाने जाते हैं। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, अनुभव और सक्रिय कार्यशैली को देखते हुए पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें यह महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति पर मनीष यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, भाजपा प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश संयोजक कस्तूबानंद जोशी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है, वे उस पर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे।मनीष यादव की नियुक्ति पर संपूर्ण सिंह रावत, परिपूर्णानंद मिश्रा, शेखर कश्यप, सुखदेव चौहान, गणेश उनियाल,सुरेश सैनी, भारत मनचंदा, महावीर असवाल, नरेंद्र उनियाल, रामकिशन, संदीप तड़ियाल, अर्चित गौतम,नितिन पवार, महेश पंत मौजूद रहे।

एक बड़े बैंक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया

हल्द्वानी संवाददाता. नगर में एक बड़े बैंक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बैंक में हल्द्वानी निवासी युवक के खाते पर पिथौरागढ़ निवासी व्यक्ति को लाखों का लोन दे दिया गया। फर्जीवाड़े का पता चलने पर पीड़ित ने बैंक के साथ साथ पुलिस को भी मामले से अवगत कराया है। भोटिया पड़ाव निवासी एक युवक ने बताया कि उसके पिता का निजी बैंक में खाता है। आरोप लगाया कि बीते दिन किसी काम से वह बैंक में गए तो पता चला कि उनके नाम पर पिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति ने दो बार लाखों रुपये का लोन ले लिया। आरोप लगाया कि एक बार पांच लाख तो दूसरी बार 10 लाख का लोन बैंक द्वारा दे दिया गया है। पता चला कि लोन लेने वाला किस भी लगातार भर रहा है, जिससे आशंका जताई है कि बैंक की तरफ से खाते से लापरवाही के कारण ऐसा हुआ होगा। पीड़ित ने बैंक स्टाफ को मामले से अवगत कराया है। साथ ही पुलिस को लिखित में शिकायत दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। लोन का यह सिलसिला 2022 ये चल रहा है। पुलिस के मुताबिक तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

मंडल अध्यक्ष अरुण जोशी ने मंडल के अंतर्गत सभी मोर्चों की कार्यकारिणी का गठन

लालकुआं संवाददाता. भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट की सहमति के उपरांत लालकुआं मंडल अध्यक्ष अरुण जोशी ने मंडल के अंतर्गत सभी मोर्चों की कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। इस क्रम में भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिम्मेदारी तारा पांडे को सौंपी गई है।महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाए जाने पर तारा पांडे ने जिला व मंडल नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है, उसका वह पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करेंगी। तारा पांडे ने कहा कि महिला मोर्चा के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाया जा सके. उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर वह अभी से सक्रिय रूप से तैयारी में जुट गई हैं। इसके लिए एक मजबूत और समर्पित टीम का गठन किया जा रहा है, जो पार्टी हित में निरंतर कार्य करेगी और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य करेगी।जिलाध्यक्ष सहित मंडल अध्यक्ष अरुण जोशी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि सभी मोर्चे संगठन की रीति-नीति के अनुरूप कार्य करते हुए पार्टी को नई मजबूती प्रदान करेंगे।

एक व्यक्ति को गांजे के साथ गिरफ्तार

रामनगर संवाददाता. कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है।कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने दीपक प्रकाश उर्फ अधौरी पुत्र आनन्द प्रकाश निवासी जोगीपुरा को गौरे सरदार की बगल वाली गली के पास बगीचे से मुखबिर की सूचना पर कुल 05.320 किग्रा अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया।कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है।इस दौरान पुलिस टीम में एसआई सोमेन्द्र सिंह,एसआई तालिब हुसैन, कांस्टेबल महबूब आलम, कांस्टेबल भूपेन्द्र सिंह, कांस्टेबल संजय कुमार शामिल रहें।

हल्द्वानी रामनगर मार्ग बेलगड़ के पास टला बड़ा हादसा टला,बाइक सवार को बचाने में रोडवेज बस सड़क किनारे धंसी, 7 यात्री घायल

रामनगर संवाददाता. हल्द्वानी से हरिद्वारख्रदेहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की रोडवेज बस एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। यह दुर्घटना रामनगर के पास हल्द्वानीख्ररामनगर राज्य मार्ग पर बेलगड़ क्षेत्र के पास उस समय हुई, जब बस चालक ने अचानक सामने आए एक बाइक सवार को बचाने का प्रयास किया।इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे धंस गई।प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार बस संख्या यूके 04 पीए 1681 हल्द्वानी से चलकर देहरादून की ओर जा रही थी। बस में उस समय करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। बेलगड़ के पास एक बाइक अचानक सामने आ गई, जिसे बचाने के लिए चालक ने तुरंत ब्रेक लगाए और बस को मोड़ने की कोशिश की। इसी दौरान बस सड़क के किनारे कच्चे हिस्से में धंस गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

होटलों का फायर रिस्क निरीक्षण, स्टाफ को दिए गए अग्नि सुरक्षा के निर्देश

अल्मोड़ा संवाददाता. अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बुधवार को फायर स्टेशन रानीखेत की टीम ने क्षेत्र के प्रमुख होटलों का फायर रिस्क निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा नरेंद्र सिंह कुंवर के पर्यवेक्षण में प्रभारी फायर स्टेशन रानीखेत गणेश चंद्र के नेतृत्व में संपन्न हुआ। निरीक्षण के दौरान होटल स्टूनवुड, पार्वती रिट्रीट और वुड्सविला होटल में मौजूद अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई।

सम्पादकीय

भारत में ही सबसे पहले गणतंत्र था

बिहार का वैशाली (लिच्छवी गणराज्य) विश्व का पहला सफल गणतंत्र माना जाता है। जब यूनान में नगर-राज्यों की अवधारणा आकार ले रही थी, उससे बहुत पहले भारत में पूरी तरह विकसित गणतांत्रिक व्यवस्थाएँ मौजूद थीं।ज् ऋग्वेद में 40 बार और अथर्ववेद में 9 बार श्गणश् शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज संख्या-बल और सामूहिक निर्णय की शक्ति को भली-भांति समझते थे। प्राचीन काल की सभा और समिति इस बात का प्रमाण हैं कि प्रजातंत्र के ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ उस समय भी सक्रिय थे।गौरव की बात है कि भारत में गणतंत्र की अवधारणा केवल 1950 से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें हमारी प्राचीन सभ्यता, वैदिक संस्कृति और इतिहास में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। पूरे विश्व को गणतंत्र का पाठ सबसे पहले इसी धरती से मिला। हमारे ही देश में सर्वप्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ, जिसकी सफलता ने संसार का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऋग्वेद और अथर्ववेद में गण, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जो लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेती थीं। श्गणश् शब्द का अर्थ ही जनता का समूह है, जहाँ शासक का चयन योग्यता के आधार पर होता था।इतिहास के प्रमाण बताते हैं कि बिहार का वैशाली (लिच्छवी गणराज्य) विश्व का पहला सफल गणतंत्र माना जाता है। जब यूनान में नगर-राज्यों की अवधारणा आकार ले रही थी, उससे बहुत पहले भारत में पूरी तरह विकसित गणतांत्रिक व्यवस्थाएँ मौजूद थीं। असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और भारत विभाजन की पीड़ा के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान आधुनिक भले ही हो, लेकिन उसकी आत्मा में श्वसुधैव कुटुंबकम्श् और श्सर्वे भवन्तु सुखिनःश् जैसी प्राचीन भारतीय भावनाएँ समाई हुई हैं। संविधान निर्माताओं ने पश्चिमी मॉडलों के साथ-साथ भारत की अपनी सांस्कृतिक विरासत और पंचायत परंपरा को भी महत्व दिया।यह दिन केवल संविधान के लागू होने का उत्सव नहीं है, बल्कि उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का अवसर भी है, जिन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत का सपना देखा था। 26 जनवरी का यह राष्ट्रीय पर्व हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसी महान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, जिसने दुनिया को लोकतंत्र की दिशा दिखाई। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित गणतांत्रिक व्यवस्थाएँ यह सिद्ध करती हैं कि भारत में लोकतंत्र कोई आयातित विचार नहीं, बल्कि हमारी अपनी मिट्टी और वेदों की मौलिक देन है। यह भी सच है कि संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था की प्रेरणा पवित्र वेदवाणी से ही ली।यह भारतीय गणतांत्रिक परंपरा की ऐतिहासिक जड़ों को उजागर करता है और साबित करता है कि लोकतंत्र और गणतंत्र की अवधारणाएँ भारत में सहस्राब्दियों पहले से मौजूद थीं। संसार के आदिग्रंथ ऋग्वेद में 40 बार और अथर्ववेद में 9 बार श्गणश् शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज संख्या-बल और सामूहिक निर्णय की शक्ति को भली-भांति समझते थे। प्राचीन काल की सभा और समिति इस बात का प्रमाण हैं कि प्रजातंत्र के ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ उस समय भी सक्रिय थे। समिति आज की संसद या लोकसभा जैसी थी, जहाँ जनता और प्रतिनिधि नीति-निर्धारण के लिए एकत्र होते थे, जबकि सभा राज्यसभा या विद्वत परिषद की तरह कार्य करती थी, जहाँ अनुभवी लोग परामर्श और न्याय का दायित्व निभाते थे।ऋग्वेद का वह मंत्र, जिसमें एकमत होकर निर्णय लेने की प्रार्थना की गई है, आधुनिक आम-सहमति के सिद्धांत का प्राचीनतम रूप माना जा सकता है। बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध के समय शलाका अर्थात मतपत्र द्वारा मतगणना का उल्लेख मिलता है, जो यह स्पष्ट करता है कि भारत में मतदान की प्रक्रिया अत्यंत विकसित थी। गण और संघ के माध्यम से बहुमत के आधार पर निर्णय लेना हमारी प्रशासनिक कुशलता का प्रतीक था। बाद में कुछ कारणों से व्यवस्था राजतंत्र की ओर मुड़ गई, लेकिन भारत की मूल चेतना हमेशा गणतांत्रिक बनी रही।आज की पीढ़ी के लिए यह प्राचीन भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था अत्यंत प्रेरक है, क्योंकि अक्सर यह मान लिया जाता है कि लोकतंत्र पश्चिम की देन है। वास्तव में गण से गणतंत्र तक की यात्रा भारत की अपनी यात्रा है। इससे हम 26 जनवरी के वास्तविक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को समझ सकते हैं। भारत के प्राचीन राजनीतिक इतिहास और विकसित संवैधानिक ढाँचे यह सिद्ध करते हैं कि आज के युग में भी हमारे लोकतंत्र की सफलता के पीछे सहस्राब्दियों पुरानी सुव्यवस्थित शासन परंपरा है।संसदीय शब्दावली की प्राचीनता इस तथ्य से समझी जा सकती है कि आज जिसे श्कोरमश् कहा जाता है, उसे प्राचीन काल में श्गणपूरकश् कहा जाता था। इसका अर्थ था कि न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति के बिना सभा मान्य नहीं होगी। सचेतक अर्थात श्व्हिपश् की अवधारणा भी तब मौजूद थी, जिससे अनुशासन बना रहता था। महर्षि पाणिनि द्वारा वर्णित वृक, यौधेय और त्रिगर्त जैसे गणराज्य प्राचीन भारत के संघीय ढाँचे के सशक्त उदाहरण हैं। महाभारत में वर्णित अंधक-वृष्णि संघ, जिसके प्रमुख श्रीकृष्ण थे, एक उन्नत गणतंत्रीय संघीय व्यवस्था का प्रतीक है।महाभारत यह भी बताता है कि जनसभा में प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार था, जो आज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रारंभिक रूप है। अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाना यह सिद्ध करता है कि सत्ता वंशानुगत नहीं, बल्कि योग्यता और जन-सहमति पर आधारित थी। कौटिल्य द्वारा लिच्छवी, वृज्जि और कम्बोज जैसे गणराज्यों का उल्लेख यह दर्शाता है कि मौर्य काल तक भी ये गणराज्य प्रभावशाली थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी में श्जनपदश् शब्द जनता की सर्वोच्चता को रेखांकित करता है।स्पष्ट है कि भारत में गणतंत्र केवल एक शासन-व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन-शैली थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाना वास्तव में उसी वैदिक, महाभारतकालीन और मौर्यकालीन लोकतांत्रिक चेतना का आधुनिक पुनर्जागरण था।

बुजुर्गों की सेवा में समय बैंक

विनीत नारायण

स्विट्जरलैंड में इस कार्यक्रम की शुरुआत बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और उनकी देखभाल की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, स्वस्थ और संवाद करने में कुशल व्यक्ति बुजुर्गों की मदद करते हैं, जैसे खरीदारी करना, कमरा साफ करना, सूरज की रोशनी में बाहर ले जाना या बस बातचीत करना। प्रत्येक घंटे की सेवा को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के व्यक्तिगत श्समय खाताश् में जमा किया जाता है।भारत जैसे देश में, जहां बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और पारंपरिक परिवार संरचना कमजोर पड़ रही है, बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकारी पेंशन योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तो हैं, लेकिन वे अक्सर अपर्याप्त साबित होते हैं। ऐसे में, स्विट्जरलैंड की श्समय बैंकश् अवधारणा एक प्रेरणादायक मॉडल प्रस्तुत करती है, जो न केवल बुजुर्गों की देखभाल को सुनिश्चित करती है बल्कि समाज में सहानुभूति और सामुदायिक भावना को भी मजबूत करती है। यह अवधारणा, जो स्विट्जरलैंड के संघीय सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है, युवाओं को बुजुर्गों की सेवा करने का अवसर देती है और बदले में उन्हें भविष्य में खुद की देखभाल के लिए श्समयश् जमा करने की अनुमति देती है। भारत सरकार को इस मॉडल को अपनाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक मूल्यों से मेल खाता है और आर्थिक बोझ को कम कर सकता है।स्विट्जरलैंड में इस कार्यक्रम की शुरुआत बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और उनकी देखभाल की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, स्वस्थ और संवाद करने में कुशल व्यक्ति बुजुर्गों की मदद करते हैं, जैसे खरीदारी करना, कमरा साफ करना, सूरज की रोशनी में बाहर ले जाना या बस बातचीत करना। प्रत्येक घंटे की सेवा को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के व्यक्तिगत श्समय खाताश् में जमा किया जाता है। जब व्यक्ति खुद बुजुर्ग हो जाता है या बीमार पड़ता है, तो वह इस जमा समय को निकाल सकता है और अन्य स्वयंसेवक उसकी देखभाल करेंगे। यह प्रणाली न केवल पैसे की बचत करती है बल्कि मानवीय संबंधों को भी मजबूत करती है।कल्पना कीजिए, एक युवा व्यक्ति जो सप्ताह में दो बार दो घंटे बुजुर्गों की सेवा करता है। एक साल बाद, श्समय बैंकश् उसके कुल सेवा समय की गणना करता है और उसे एक श्समय बैंक कार्डश् जारी करता है। इस कार्ड से वह भविष्य में श्समय और समय ब्याजश् निकाल सकता है। यानी, जमा समय पर ब्याज भी मिलता है, जो प्रोत्साहन का काम करता है। स्विट्जरलैंड में यह प्रथा अब सामान्य हो गई है और सरकार ने इसे समर्थन देने के लिए कानून भी पारित किया है। यह मॉडल पेंशन व्यय को कम करता है और समाज को अधिक सहयोगी बनाता है।भारत में इस अवधारणा को लागू करने की संभावनाएं अपार हैं। एक अनुमान के तहत, 2030 तक हमारे देश में बुजुर्गों की आबादी 19 करोड़ से अधिक हो जाएगी और कई परिवारों में बच्चे शहरों में बस जाते हैं, जिससे बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। पारंपरिक रूप से, भारत में बुजुर्गों की देखभाल परिवार की जिम्मेदारी रही है, लेकिन आधुनिकीकरण ने इस संरचना को प्रभावित किया है। श्समय बैंकश् जैसा कार्यक्रम युवाओं को प्रोत्साहित कर सकता है कि वे बुजुर्गों की सेवा करें और बदले में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिले। यह न केवल सरकारी संसाधनों पर दबाव कम करेगा बल्कि बेरोजगार युवाओं को सार्थक कार्य प्रदान करेगा।उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड की एक कहानी से प्रेरणा लें। वहां एक 67 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका क्रिस्टीना एक 87 वर्षीय बुजुर्ग की देखभाल करती थीं। उन्होंने कहा कि वह पैसे के लिए नहीं, बल्कि श्समय बैंकश् में समय जमा करने के लिए ऐसा कर रही थीं। जब वे खुद घायल हुईं, तो श्समय बैंकश् ने तुरंत एक नर्सिंग कार्यकर्ता भेजा, जो उनकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों में वे स्वस्थ हो गईं और फिर से सेवा में लग गईं। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे यह प्रणाली व्यावहारिक और प्रभावी है। भारत में भी, यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ऐसा कार्यक्रम शुरू करें, तो लाखों बुजुर्गों का जीवन बेहतर हो सकता है।हालांकि, भारत में इसे लागू करने से पहले कुछ चुनौतियों पर विचार करना जरूरी है। सबसे पहले, कार्यक्रम की प्लेटफार्म की जरूरत होगी, जहां सेवा घंटों को रिकॉर्ड किया जा सके। आधार कार्ड और डिजिटल इंडिया जैसे मौजूदा सिस्टम इसमें मदद कर सकते हैं। दूसरा, स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग जरूरी है, ताकि वे बुजुर्गों की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को समझ सकें। तीसरा, दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे कि समय निकासी के समय पहचान जांच। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी एक समस्या हो सकती है, इसलिए ऑफलाइन मोड भी विकसित किया जाना चाहिए।सरकार को दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह से शुरुआत करनी चाहिए। यदि सफल राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। कॉर्पोरेट घराने एनजीओ को अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड्स और स्थानीय समुदायों द्वारा इसे सहयोग करें। इससे न केवल बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित होगी बल्कि युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी।इस अवधारणा के सामाजिक लाभ भी कम नहीं हैं। आज के दौर में, जहां अकेलापन एक महामारी बन गया है, श्समय बैंकश् लोगों को जोड़ सकता है। बुजुर्गों से बातचीत करने से युवाओं को जीवन के अनुभव मिलेंगे, और बुजुर्गों को भावनात्मक समर्थन। यह भारतीय मूल्योंख्रजैसे श्सेवा परमो धर्मःश् से मेल खाता है। स्विट्जरलैंड में यह प्रणाली पेंशन को पूरक बनाती है, जहां पेंशन इतनी अच्छी है कि भोजन और आवास की चिंता नहीं होती, लेकिन भारत में जहां पेंशन सीमित है, यह एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है।आर्थिक दृष्टि से भी यह फायदेमंद है। भारत में बुजुर्ग देखभाल पर खर्च बढ़ रहा है नर्सिंग होम और अस्पताल महंगे हैं। श्समय बैंकश् से स्वयंसेवी देखभाल बढ़ेगी, जिससे सरकारी व्यय कम होगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि एजिंग पॉपुलेशन विकासशील देशों के लिए चुनौती है, लेकिन ऐसे नवाचारी मॉडल से इसे अवसर में बदला जा सकता है। स्विट्जरलैंड में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है और अब दुनिया के अन्य देशों को इसे अपनाना चाहिए।भारत सरकार केंद्र और राज्य स्तर पर को इस श्समय बैंकश् अवधारणा पर विचार करना चाहिए। इसे लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाए, जो स्विट्जरलैंड के मॉडल का अध्ययन करे और भारतीय संदर्भ में अनुकूलित करे। यदि हम आज कदम उठाएं, तो कल के बुजुर्गख्रजो आज के युवा हैंख्रएक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। यह न केवल एक नीति है, बल्कि मानवता का निवेश है। समय सबसे मूल्यवान मुद्रा है और इसे बैंक में जमा करने का विचार दुनिया को बदल सकता है। आइए, हम इसे अपनाएं और एक बेहतर समाज बनाएं।

संदेश नाकारात्मक है

जिस समय मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत से वार्ता अंतिम दौर में है और इसी हफ्ते उसकी घोषणा की आशा है, जीएसपी के तहत मिली छूट की सुविधा हटाने के ईयू के कदम से नकारात्मक संदेश गया है।

भारतीय उत्पादों से सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली (जीएसपी) के तहत मिली छूट को हटा लेने के यूरोपियन यूनियन (ईयू) के फैसले पर केंद्र ने कहा है कि भारतीय निर्यात पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। सरकार का दावा है कि इससे भारत के सिर्फ 2.66 प्रतिशत निर्यात प्रभावित होंगे। जबकि ईयू मुख्यालय से आई खबरों में बताया गया है कि जीएसपी छूट वापस होने से वस्त्र, प्लास्टिक, धातु, इंजीनियरिंग साग्रियां सहित लगभग 87 फीसदी भारतीय निर्यात यूरोपीय बाजार में बांग्लादेश या वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के उत्पादों की तुलना में महंगे हो जाएंगे। जिस समय मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत से वार्ता अंतिम दौर में है और इसी हफ्ते उसकी घोषणा की आशा है, बेशक ईयू के इस कदम से नकारात्मक संदेश गया है।एक समझ यह है कि इससे व्यापार वार्ता में भारत की स्थिति कमजोर हुई है। जो छूट दशकों से हासिल थी, उसे बहाल कराना भी अब इस वार्ता में भारत का एक मकसद हो जाएगा। दूसरी तरफ उन रियायतों को ईयू भारत के लिए नई छूट के रूप में पेश कर सकता है। पहले ही सहमति ना बनने के कारण कृषि एवं निवेश संरक्षण जैसे क्षेत्रों को फिलहाल प्रस्तावित समझौते से अलग रखने का फैसला हुआ है। ईयू के कार्बन टैक्स का मुद्दा अभी अनसुलझा है। इस बीच मदर ऑफ ऑल डील्स तथा रक्षा एवं सुरक्षा समझौता होने जैसी बातें कही जरूर गई हैं।मगर यह भी साफ किया गया है कि 27 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली भारत-ईयू शिखर बैठक के दौरान समझौतों पर दस्तखत नहीं होंगे। इस बारे में सिर्फ आम सहमति बनने की घोषणा ही अपेक्षित है। गौरतलब है कि ईयू से मुक्त व्यापार समझौते की बात दशक पुरानी हो चुकी है। डॉनल्ड ट्रंप के दौर में बने अमेरिकी दबाव के कारण ईयू और भारत दोनों नए सहभागी ढूंढने को मजबूर हुए हैं, तो इस वार्ता को तरजीह मिली है। मगर अड़चनें अभी बरकरार हैं। इसी बीच ईयू ने जीएसपी सुविधा हटा कर अटकलों को हवा दी है।

सूबे के 544 नये विद्यालयों में संचालित होंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम

- योजना के तहत 8 व्यावसायिक विषयों में दक्ष होंगे छात्र-छात्राएं
- अबतक व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर चुके 146 छात्रों को मिला कैम्पस प्लेसमेंट

देहरादून संवाददाता. सूबे में समग्र शिक्षा के तहत 544 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जायेगा, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। इन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पारम्परिक विषयों के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा दी जायेगी, जिससे वह व्यावहारिक व तकनीकी कौशल में दक्ष होंगे साथ ही भविष्य में रोजगार व स्वरोजगार के लिये भी सक्षम हो सकेंगे। योजना के तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र से छात्र-छात्राओं को 8 विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा दी जायेगी। नवीन स्वीकृत विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शीघ्र संचालन को विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये गये हैं। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में एनईपी-2020 के अनुरूप विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है। इसी क्रम में समग्र शिक्षा एवं पीएम-श्री योजना के तहत प्रदेश के 544 और नये विद्यालयों का चयन व्यावसायिक शिक्षा के संचालन को किया गया है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दे दी गई है। इन विद्यालयों में इसी शैक्षणिक सत्र से 8 विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जाएगा। जिसमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रोनिक्स एंड हार्डवेयर, आईटी, पलम्बिंग, रिटेल तथा टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी शामिल है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन सभी सेक्टर को उत्तराखंड बोर्ड व सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जिन्हें विद्यालय स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जायेगा। उक्त व्यावसायिक विषयों में कक्षा-10 व 12 के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के माध्यम से क्रमशः लेवन-3 व 4 के दक्षता प्रमाण पत्र दिये जायेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के संचालन को पीएसएससीआईवीई (पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान) के मानकों के अनुरूप 548 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अनुभवी प्रशिक्षकों की तैनाती निर्धारित योग्यता के अनुरूप की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि उक्त विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालन के लिये प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, शासनादेश के उपरांत व्यावसायिक शिक्षा के संचालन को विभागीय स्तर पर निविदा आयोजित की जायेगी। विभागीय अधिकारियों के बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 531 विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इन विषयों में कुल 50903 छात्र-छात्राएं पंजीकृत है। जिसमें 27561 छात्राएं व 23342 छात्र शामिल हैं। इसके अलावा 28 हब्स एंड स्पोक विद्यालय भी संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें 612 छात्राएं व 361 छात्र सहित कुल 973 बच्चे शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके तहत एयरोस्पेस एंड एविएशन तथा फूड इंडस्ट्री सेक्टर के संचालन को भी भारत सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है। जिसे उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के तहत कक्षा-12 के प्रथम बैच में अध्ययनरत छात्रों के लिये राज्य स्तरीय जॉब फेयर आयोजित किया गया, जिसमें 146 छात्रों को विभिन्न कंपनियों द्वारा जॉब ऑफर कर दिये गये।

वन विभाग की महिलाकर्मी को सम्मोहित कर जेवर और नकदी ठगे

देहरादून संवाददाता. ड्यूटी जा रही वन विभाग की एक महिला कर्मचारी को तीन शातिरों ठगों ने तंत्र-मंत्र का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया। पटेलनगर थाना क्षेत्र चंद्रबनी चौक के पास आरोपी दिनदहाड़े सोने के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर पटेलनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। पीड़िता पूनम पंवार निवासी कारबारी ग्रांट अपने घर से ट्रांजिट हॉस्टल चंद्रमणी (ड्यूटी) जाने के लिए निकली थीं। जैसे ही वह चंद्रबनी चौक के पास पहुंचीं, एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बातों में उलझा लिया। इसी बीच दूसरा व्यक्ति वहां पहुंचा और उनके बारे में निजी जानकारी पूछने लगा। तभी एक तीसरा व्यक्ति वहां आया और दावा करने लगा कि वह और उसके पिता तंत्र-मंत्र के जानकार हैं। उसने अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए जमीन से मिट्टी और कागज उठाया।

जमीन की डील कई लोगों से कर लाखों ठगने में मां-बेटियों और दामादों पर मुकदमा

देहरादून संवाददाता. पटेलनगर क्षेत्र के शीशमबाड़ा इलाके में एक ही जमीन का सौदा कर अलग-अलग लोगों से लाखों रुपये हड़प लिए गए। एक पीड़ित की शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को आरोपी महिला, उसकी बेटियों और दामादों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत करने वाले पीड़ित से बीस लाख रुपये ठगे गए। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि विकासनगर के धर्मावाला निवासी विकास धानिया ने तहरीर दी। बताया कि उन्होंने मौजा शीशमबाड़ा स्थित खसरा नंबर-360 और 362 की कुल 0.1129 हेक्टेयर जमीन का सौदा प्रमिला से किया था। इसके एवज में 15 लाख रुपये नकद बतौर ब्याना दिए गए थे और रजिस्ट्री की तारीख 28 जुलाई 2025 तय हुई थी। तय तारीख पर विकास धानिया सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे और शाम तक इंतजार किया। बेचने वाला पक्ष वहां नहीं पहुंचा। संपर्क करने पर आरोपियों ने बहाना बनाया और जल्द रजिस्ट्री की बात कही। इसके बाद विश्वास में लेकर आरोपियों ने विकास से आरटीजीएस के जरिए पांच लाख रुपये और ले लिए। इस तरह कुल 20 लाख रुपये देने के बाद भी जब जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई तो पीड़ित ने छानबीन शुरू की। छानबीन में विकास को पता चला कि आरोपियों ने उसी जमीन का सौदा बडोवाला निवासी सोमेश से करके करीब 23 लाख रुपये और सहारनपुर निवासी अमन कुमार व राहुल कुमार से नौ लाख रुपये पहले ही ले रखे हैं। आरोप है कि शातिर परिवार ने एक ही संपत्ति को अलग-अलग लोगों को दिखाकर कुल 52.05 लाख रुपये की ठगी की है। विकास धानिया का आरोप है कि जब उन्होंने अपने रकम मांगी या रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया तो आरोपी महिला, उसकी बेटियां (शीतल, मोनिका, दीपिका, मीनाक्षी) और दामाद (नीरज, रवि) उन्हें झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने लगे। इंस्पेक्टर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी से रकम हड़पने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस के महत्व पर डाला प्रकाश

ऋषिकेश संवाददाता. हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एचआईएमएस) जौलीग्रांट में क्लीनिकल रिसर्च और चिकित्सा नैतिकता (मेडिकल एथिक्स) की बारीकियों को समझाने के लिए पांच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज गुरुवार को हुआ। इस दौरान विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य सेवाओं में ईमानदारी और गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस (जीसीपी) के महत्व पर प्रकाश डाला। संस्थान के क्लीनिकल रिसर्च विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना से हुई। मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य डॉ. रेनू धस्माना ने कहा कि एक चिकित्सक और मरीज का रिश्ता केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अटूट विश्वास और सहानुभूति पर टिका होता है। डॉ. किरण भट्ट ने जोर दिया कि शोध की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मरीजों की सुरक्षा और रिसर्च की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। इसके लिए गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस नियमों का पालन अनिवार्य है। डॉ. डीसी धस्माना ने पेशेवरों को प्रेरित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियामक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना हर चिकित्सक की पेशेवर जिम्मेदारी है। कार्यक्रम की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. निक्कू यादव ने बताया कि इस पांच सप्ताह के प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को क्लीनिकल रिसर्च के व्यावहारिक पहलुओं से रूबरू कराया जाएगा। डॉ. तरुणा शर्मा, डॉ. अनुराधा कुसुम, डॉ. रुचि जुयाल, डॉ. मनीषा शर्मा, आकांक्षा उनियाल आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार...

डीआईटी विश्वविद्यालय के छात्र को मिला राष्ट्रीय गौरव

देहरादून संवाददाता. डीआईटी विश्वविद्यालय के सीनियर अंडर ऑफिसर उत्कर्ष शर्मा ने गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में आयोजित अखिल भारतीय गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व किया। साथ ही प्रधानमंत्री रैली की कमान भी संभाली। उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें गुरुवार को विवि में सम्मानित किया गया। उत्कर्ष विवि में बीटेक (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) तृतीय वर्ष के छात्र हैं एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) 29 उत्तराखंड बटालियन के कैडेट हैं। उनका चयन उत्तराखंड निदेशालय से गणतंत्र दिवस समारोह (आरडीसी)-2026 के लिए हुआ था। डीआईटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. जी. रघुराम ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि सीनियर अंडर ऑफिसर उत्कर्ष शर्मा की यह उपलब्धि पूरे विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है और वे उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है।

गोदाम के बाहर से लोडर चोरी

देहरादून संवाददाता. ब्राह्मवाला चौक के पास गोदाम के बाहर पार्क किया गया लोडर वाहन (छोटा हाथी) रात में चोरी हो गया। स्थानीय निवासी गजाला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका लोडर बीते 23 जनवरी की रात घर से कुछ दूर एक गोदाम के पास पार्क किया गया था। लोडर में कबाड़ और डिजिटल कांटा रखा था। अगले दिन सुबह देखा तो वाहन चोरी हो गया था। सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो दो व्यक्ति लोडर चोरी करते हुए दिखाई। उन्होंने बुधवार को पटेलनगर कोतवाली में लिखित तहरीर दी। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि शिकायत अज्ञात के खिलाफ चोरी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सराहा

देहरादून संवाददाता. उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी कमेटी के प्रस्ताव पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया है। प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि एक तरफ छात्र अभी माध्यमिक परीक्षा की तैयारियों में जुटे हैं और इधर यूजीसी कमेटी के विवाद से पूरे उत्तरभारत मंे विश्वविद्यालयों के सामान्य छात्र एवं कई संस्थाएं व संगठन सड़कों पर आने को विवश हो गये। केन्द्र सरकार व उच्चशिक्षा मंत्री द्वारा लगातार प्रदर्शन एवं नाराजगी की अनदेखी की और कोई पहल नहीं की जिससे लोगो में नाराजगी थी। इस काले कानून को देखते हुये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा भी 01 फरवरी को शहीद स्मारक में बैठक बुलाई थी।

सांई धाम के पूजन में पहुंचे कोश्यारी

देहरादून संवाददाता. ऊं साई नारायण सेवा धाम शास्त्रीनगर में गुरुवार को हुए हवन, आरती, भंडारे में अन्य भक्तों के साथ पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हुए। सेवाधाम पदाधिकारियों ने पद्मभूषण की घोषणा पर खुशी जताई और उनका स्वागत किया। पूजन भंडारे में राजीवनगर, दीपनगर, बद्रीपुर, डिफेंस कॉलोनी, सारथी विहार, नेहरु कॉलोनी के श्रद्धालु भी शामिल हुए। सेवा धाम संस्थापिका लाजवंती पेटवाल ने बताया कि एक फरवरी को डिफेंस कॉलोनी सामुदायिक भवन में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। आयोजक पार्षद राकेश पंडित ने साई धाम आकर सभी भक्तों से सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह किया।

मसूरी में धूप खिली, पाला पड़ने से परेशानी

देहरादून संवाददाता.पर्यटन नगरी में बर्फबारी के बाद धूप खिली। इससे लोगों को राहत मिली है। भारी मात्रा में पाला पड़ने से वाहनों के शीशे पर पाले की मोटी परत जम गई। मकानों की छत बर्फ की तरह सफेद हो गई। बर्फबारी के बाद भले ही मौसम खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है लेकिन पाला पड़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान खुलने से लोगों ने गुनगुनी धूप का आनंद लिया लेकिन रात को पाला गिरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। जिन स्थानों पर बर्फ अभी पिघली नहीं है वहां पर फिसलन हो रही है। रोड पर खड़े वाहनों के शीशों पर पाले की मोटी परत जम गई है। जहां पानी गिरता है वहीं जम रहा है। हालांकि धूप खिलने से पाला पिघल रहा है। दूसरी ओर लंबे इंतजार के बाद मसूरी के आस पास के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई जमकर बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल गए । बर्फबारी होने से खेतों को अच्छा पानी मिल गया व जो फसलें सूख रही थी उनमें जान आ गई है। फलों के पेड़ों को भी इसका लाभ मिला है। खासकर गेहूं व अन्य फसलें जो इस मौसम में बोई गयी हैं उन्हें लाभ मिला है। इसी तरह सेब, आड़ू, खुबानी, प्लम, अखरोट आदि फलों के लिए भी बर्फबारी बहुत उपयोगी होती है।

पुलिस जवानों की समस्याएं सुनीं, 36 जवान भी नवाजे

हरिद्वार संवाददाता. रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में गुरुवार को हुए सैनिक सम्मेलन में जवानों की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याएं सुनी गईं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल न केवल जिला प्रभारी, बल्कि पुलिस परिवार के अभिभावक की भूमिका में नजर आए। इसके साथ ही, जनसेवा और अपराध के खुलासे पर पांच महिला कर्मियों समेत 36 जवानों को सम्मानित किया गया। चयनित कार्मिकों को दिसंबर-2025 के लिए 'पुलिस मैन ऑफ द मंथ' सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान कई मामलों का मौके पर निस्तारण कराया गया, जबकि शेष प्रकरणों के समाधान के लिए अफसरों को निर्देश दिए गए। एसएसपी ने साफ कहा कि पुलिस बल की कार्यक्षमता तभी बेहतर हो सकती है, जब जवान मानसिक रूप से संतुष्ट और समस्यामुक्त हों। इस सम्मेलन में वेतन, आवास, स्थानांतरण, ड्यूटी समय सहित तमाम विषयों पर चर्चा की गई। इधर, सम्मान पाने वालों में कोतवाली नगर से कांस्टेबल राहुल धनिक, कलियर से उपनिरीक्षक सूरज नेगी एवं हेड कांस्टेबल सोनू कुमार शामिल रहे।

नगर मंडल अध्यक्ष फईम कुरैशी का ग्राम टांडा स्थित अपने कार्यालय पर जोरदार स्वागत

रामनगर संवाददाता.भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि इंदर सिंह रावत ने नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हूर अली खान और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष फईम कुरैशी का ग्राम टांडा स्थित अपने कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया। इंदर सिंह रावत ने कहा कि दोनों से संगठन को और अधिक मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने दोनों पदाधिकारियों से भाजपा को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने का आह्वान किया।दोनों पदाधिकारियों ने भाजपा संगठन को मजबूत बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा संगठन को मजबूत करने और भाजपा प्रत्याशी को जिताने का काम किया जाएगा। नवनियुक्त पदाधिकारियों को विधायक दीवान सिंह बिष्ट, भाजपा के वरिष्ठ नेता इंदर सिंह रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत, भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह खाती, पूर्व पालिकाध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, पीरुमदारा मंडल अध्यक्ष बलदेव सिंह रावत, भाजपा नेता शिशुपाल सिंह रावत, भाजपा नेता विपिन कांडपाल, शोभा कांडपाल,भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत,भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष सैयद अली नकवी, भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री अजीज खान, मोहम्मद आदिल, डॉक्टर तनवीर अख्तर, इकबाल हुसैन, जिकरान कुरैशी,अनवर मालिक, दानिश सिद्दीकी सरफराज अहमद आदि लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है।

गरीब मजदूरों का हक छीन रही भाजपा

ऋषिकेश संवाददाता. कांग्रेस ने छिद्दरवाला क्षेत्र में चौपाल लगाकर भाजपा की खामियां बताई। कहा कि भाजपा गरीब मजदूरों का हक छीन रही है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर मनरेगा को धीरे-धीरे समाप्त करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि मनरेगा योजना देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी थी, लेकिन भाजपा सरकार की गलत नीतियों और जनविरोधी फैसलों के कारण आज यह योजना कागजों तक सीमित होकर रह गई है। रोजगार के अभाव में गांवों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल व ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल रमोला ने कहा कि जब सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, तो फिर गरीब मजदूरों को उनका मेहनताना समय पर क्यों नहीं मिल रहा। चेतावनी दी गई कि यदि भाजपा सरकार ने मजदूरी का तत्काल भुगतान नहीं किया, तो ग्रामीण सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी, विधानसभा बीएलए गजेंद्र विक्रम शाही, ज्येष्ठ प्रमुख धनबीर बेंदवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्र सिंह राणा, धन पाल सिंह, त्रिलोक सिंह, विजय रावत, सुरेंद्र खुराना, तेजपाल सिंह कलूड़ा, राजपाल सिंह, सत्य सिंह बिष्ट, हरि सिंह राणा, हरभजन सिंह, सूरत सिंह रांगड, के के थापा, विजय सिंह बिष्ट, राकेश कंडियाल, मोहन सिंह, कुंवर सिंह गुसाई, कमल रावत, राकेश गौड, प्रवीण मिश्रवाण, प्रताप छेत्री, सुमति मिश्रवाण, वीरा देवी, विमला असवाल, बसंती देवी मिश्रवाल, सरोजनी देव रमोला, मंजू सेमवाल, मीनाक्षी बिष्ट, पेरालाल, निर्मल सिंह मिश्रवाण, दीप चंद पंवार, जय बहुगुणा, काव्यांश रमोला और आनन्द सिंह नेगी आदि मौजूद थे ।

शाइनिंग स्टार स्कूल के अंग्रेजी प्रवक्ता पीसी दानू आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी देहरादून के द्वारा सम्मानित

रामनगर संवाददाता. शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु नगर के शाइनिंग स्टार स्कूल के अंग्रेजी प्रवक्ता पीसी दानू को आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी देहरादून के हॉल में विशिष्टजनों के द्वारा शिक्षाविद अवार्ड से सम्मानित किया गया साथ ही अलग-2 क्षेत्रो में योगदान देने वाली हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। अपनी योग्यता व कर्त्तव्यनिष्ठा के दम पर छात्र-छात्राओं में ज्ञान की अलख जलाकर श्री दानू के द्वारा तराशे जा रहे छात्र-छात्राओं के द्वारा समय-2 पर विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल व रामनगर व उत्तराखंड का नाम रोशन किया जा रहा है। श्री दानू की इस उपलब्धि पर उन्हें स्कूल के डायरेक्टर डीएस नेगी, प्रिंसिपल तुलसी सिंह, राजेन्द्र सिंह, केसर राणा, जीडी जोशी, रोहित नेगी, रोहित रावत, स्वेता सिंह, पिंकी रावत, कविता पांडे, चेतना आर्या, रेनू बुडलाकोटि, शबनम मंसूरी, महिमा छावड़ा, चंद्रा रावत, सरिता नेगी, कुलदीप रावत, सुखजीत रावत, विशाल अग्रवाल, दीपक रावत, दीपाली नेगी, पूनम नेगी, मोनिका नेगी, दीपिका रावत, लक्ष्मी, लता खाती, कीर्ति टम्टा, खुशी अरोरा, प्रियंका बिष्ट, रानी, देवेंद्र आनंद आदि टीचर्स सहित अभिभावकों व स्कूल स्टाफ ने बधाई देते हुये खुशी का इजहार किया है।

राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता वार्षिक सम्मेलन संवाद-2026 का आयोजन

रामनगर संवाददाता. उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता वार्षिक सम्मेलन संवाद-2026 का आयोजन रामनगर के आमडंडा क्षेत्र में किया गया। खास बात यह रही कि यह संवाद कार्यक्रम 12-13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुआ, जिसमें देश के 20 राज्यों से आए क्रेता (बायर्स) शामिल हुए, जो वन निगम से लकड़ी क्रय करते हैं। सम्मेलन में लकड़ी के रेट्स, निकासी प्रक्रिया, पारदर्शिता और समन्वय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल, वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्रेता-विक्रेता के बीच रिश्तों को मजबूत करना, व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाना, सीधे संवाद का मंच देना और बायर्स की अपेक्षाओं को समझकर उन्हें क्रियान्वित करना रहा। सम्मेलन का स्लोगन "व्यवहार से व्यापार तक" रहा, जिसे व्यापार की बुनियादी आवश्यकता बताया गया।वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड वन विकास निगम राज्य को बड़ा राजस्व देने वाला एक महत्वपूर्ण कॉरपोरेशन है। राज्य का लगभग 71 प्रतिशत क्षेत्र वन आधारित है। वन विभाग द्वारा आवंटित लकड़ी को निगम काटकर व्यवसाइयों को उपलब्ध कराता है, जिससे निगम लगातार प्रगति कर रहा है और राज्य को अच्छा राजस्व मिल रहा है। हालांकि, अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है।उन्होंने वियतनाम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लकड़ी उद्योग से मिलियन डॉलर का निर्यात किया जा रहा है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में वुड-बेस्ड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। साथ ही राज्य में मौजूद जड़ी-बूटी की अपार संभावनाओं को देखते हुए, वन पंचायतों के माध्यम से 628 करोड़ रुपये की हर्बल मिशन योजना शुरू की गई है। इसमें वन निगम को जोड़कर बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज तैयार किया जाएगा, जिससे वन पंचायतों की आय बढ़ेगी और स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत होगी।सम्मेलन के दौरान राजनीतिक सवालों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए वन मंत्री ने अंकिता मामले में कहा कि सरकार ने शुरू से ही त्वरित कार्रवाई की, अपराधियों को सजा दिलाई और तथाकथित वीआईपी एंगल पर सीबीआई जांच के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।वहीं कोसी नदी में अवैध खनन के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई वीडियो या शिकायत संज्ञान में आती है तो जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में वन विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए हैं और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इस दौरान विधायक दीवान सिंह बिष्ट,पूर्व राज्यमंत्री डॉक्टर निशांत पपने, मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल धीरज पांडे,कार्बेट के डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा, कार्बेट के एसडीओ अमित ग्वासीकोटि,डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य,डीएफओ ध्रुव मर्तोलिया एसडीओ संदीप गिरी, एसडीओ अंकित बडोला,डीएलएम ललित आर्य, डीएसएम वन निगम मुदित कुमार आदि मौजूद रहें।

ऋषिकेश में 16 मार्च से होगा योग महोत्सव

ऋषिकेश संवाददाता. तीर्थनगरी ऋषिकेश में 16 से 22 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाले योग महोत्सव की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग ने गुरुवार को योगाचार्यों और पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर तैयारियों पर चर्चा की। मुनिकीरेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिसॉर्ट में बैठक के दौरान योग शिक्षकों से सुझाव लिए गए। राजश्री योगशाला, श्यामपुर के निदेशक धनीराम बिंजोला ने सुझाव दिया कि क्षेत्र के सभी योग शिक्षकों के नाम और संपर्क नंबर गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध किए जाएं, जिससे देश-विदेश से आने वाले योग साधकों को सही जानकारी मिल सके। योगाचार्य वेदप्रकाश मैठाणी ने योग महोत्सव के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि इसमें अंतरराष्ट्रीय योग विद्यार्थियों और विदेशी पर्यटकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ताकि ऋषिकेश की वैश्विक योगनगरी की पहचान और सशक्त हो। गढ़वाल मंडल विकास निगम के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष योग महोत्सव का आयोजन 16 से 22 मार्च 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव को भव्य और सफल बनाने के लिए स्थानीय योगाचार्यों और पर्यटन विशेषज्ञों से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। बैठक में भरतचंद्र, दीपक रावत और कनिका आनंद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

सहायक स्टांप आयुक्त ने किया निरीक्षण

ऋषिकेश संवाददाता. सहायक स्टांप आयुक्त रेखा नेगी ने गुरुवार को सब रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्री की नकल और मूल दस्तावेज देने समेत अन्य कार्यों की गहन जांच की। आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए रजिस्ट्री कार्यों में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। निरीक्षण के दौरान सब रजिस्ट्रार हरीश चंद्र चौहान ने बताया कि कार्यालय में रजिस्ट्री और अन्य कार्य सुचारु रूप से संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने डीएम के निरीक्षण में निबंधक लिपिक के रजिस्ट्री कार्य को लेकर खड़े किए सवाल पर भी जवाब दिया। बताया कि शासन की ओर से सब रजिस्ट्रार की सरकारी कार्यों के चलते अनुपस्थिति में लिपिक रजिस्ट्री की कार्यवाही को कर सकते हैं। हालांकि, इसमें अंतिम हस्ताक्षर और अन्य कार्य सब रजिस्ट्रार के माध्यम से ही पूरा होना है। उन्होंने बताया कि कार्यालय में लिपिक के सृजित पदों में से भी महज एक लिपिक वर्तमान में तैनात है।

लायंस क्लब ने निशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया

ऋषिकेश संवाददाता. लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन की ओर से ग्राफिक एरा हास्पिटल देहरादून के सहयोग से आयोजित निशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर में वरिष्ठ नागरिक समेत क्षेत्रवासियों ने बढ़-चढ़कर लाभ लिया। वक्ताओं ने हृदय एवं न्यूरो संबंधी रोगों की जांच की और आवश्यक परामर्श दिया। कहा कि रोग व स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूकता से कई रोगों से बचा जा सकता है। गुरुवार को व्यापार सभा में आयोजित शिविर में ग्राफिक एरा हास्पिटल देहरादून के निदेशक कार्डियक साइंसेज डॉक्टर अखिलेश पांडेय और डॉ. विशेष सलाहकार न्यूरोसर्जरी पेयोज पांडे ने मरीजों की स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक चिकित्सा परामर्श दिया। उन्होंने मुफ्त ईसीजीसी, शुगर जांच, ब्लड प्रेशर आदि जांच की। कई जरूरतमंदों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान डॉ. अखिलेश पांडेय ने प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को हृदय संबंधी बीमारियों के प्रति भी जागरूक किया और बचाव के उपाय बताए। मुख्य अतिथि मेयर शंभू पासवान ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बेहद आवश्यक है। व्यापार सभा अध्यक्ष मनोज कालरा ने कहा कि कई जरूरतमंद धन के अभाव में चिकित्सा सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, शिविर का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ पहुंचााना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनीत चावला ने की।

विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी

ऋषिकेश संवाददाता. ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल रायवाला गांव में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। अग्रवाल ने ग्रामीणों की जनसमस्याएं सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों से फोन पर वार्ताकर समस्याओं के शीघ्र निवारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सागर गिरी ने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों गंगा किनारे बाढ़ सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया। क्षेत्र पंचायत सदस्य अनूप नेगी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर सहयोग देने पर विधायक का धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्यमंत्री ने रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की

-युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

देहरादून संवाददाता. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन एवं उद्योग क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के माध्यम से लोगों को इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए, ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का समय पर एवं पूरा लाभ मिले, इस पर सभी विभाग विशेष ध्यान दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवंटित बजट का पूर्ण आउटकम प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उच्च स्तरीय बैठकों के कार्यवृत्त उन्नति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं। उन्होंने सेब की अतिसघन बागवानी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी ढंग से संचालित कर निर्धारित लक्ष्यों को समय से प्राप्त किया जाए तथा किसानों को अधिकाधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों से संबंधित देयकों का भुगतान समय पर हो। किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहद उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड में व्यापक संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए 'हनी मिशन' के अंतर्गत शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाएं। राज्य में शहद का आॅर्गेनिक सर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बागवानी एवं मौन पालन के क्षेत्र में जिन राज्यों में अच्छा कार्य हुआ है, उनके अध्ययन हेतु अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की टीमें उन राज्यों में भेजी जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 29 उत्पादों को जी.आई. टैग प्राप्त हुआ है, जिनमें से 18 कृषि एवं कृषि कल्याण से संबंधित हैं। इस वर्ष 25 अन्य उत्पादों को जी.आई. टैग के लिए चिन्हित किया जाएगा। राज्य में 134 करोड़

रुपये की लागत से लागू स्टेट मिलेट पॉलिसी के अंतर्गत मंडुवा, झंगोरा, रामदाना, कौणी एवं चीना को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल के 24 विकासखंडों तथा द्वितीय चरण में 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल के 44 विकासखंडों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में 5 हजार से अधिक गांवों को आच्छादित कर लगभग डेढ़ लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया है। मिलेट फसलों की क्रय-विक्रय हेतु 216 क्रय केंद्र खोले गए हैं तथा सहकारिता विभाग के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड बनाया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5 हजार मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 5,386 मीट्रिक टन मिलेट फसलों का क्रय किया जा चुका है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत चार वर्षों में 32 हजार के लक्ष्य के सापेक्ष 33,620 लाभार्थियों को 202.72 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। आगामी वर्ष में 9 हजार लोगों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निधारित किया गया है।

पर्यटन विभाग के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत चार वर्षों में 780 होम स्टे स्थापित किए गए हैं, जिसके लिए 188.58 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चार वर्षों में एक हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कुल 105 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का वित्त पोषण किया गया है। राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन क्षेत्र में 17,450 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश झा, दिलीप जावलकर, विनय शंकर पाण्डेय, एस.एन. पाण्डेय, वी. षणमुगम, धीराज गर्ब्याल सहित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

गौमाता में बसती है सनातन की आत्मा: सतपाल महाराज

देहरादून संवाददाता. सनातन की आत्मा गौमाता में निवास करती है। आज के समय में जब समाज अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है। ऐसे में गौमाता की गुम होती भूमिका और महत्व को समझाने का प्रयास फिल्म 'गोदान' के माध्यम से किया गया है। ये बात पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को सुभाष रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'गोदान' के टीजर, गीत और पोस्टर लांच के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहाँ अब पारंपरिक कहानियों के साथ-साथ सामाजिक विषयों और वैचारिक मुद्दों पर भी सार्थक फिल्में बन रही हैं। महाराज ने बताया कि विनोद चौधरी के निर्देशन में बनी फीचर फिल्म 'गोदान' 6 फरवरी 2026 से देशभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी।

उत्तराखण्ड में पहली बार पीएलएफएस सर्वेक्षण शुरू, रोजगार आंकड़ों का होगा सटीक आकलन

देहरादून संवाददाता. अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड (नियोजन विभाग) द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अंतर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान (आईआरडीटी), सर्वे चौक, देहरादून में किया गया। यह सर्वेक्षण भारत सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय की सामाजिक-आर्थिक इकाई के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार वर्ष 2017 से पीएलएफएस का संचालन कर रही है, जबकि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस सर्वेक्षण को पहली बार राज्य के सभी जनपदों में किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में संचालित होगा और इसे अर्थ एवं संख्या विभाग के जनपद एवं विकासखण्ड स्तरीय कार्मिकों द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम के तहत संपादित किया जाएगा। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य में श्रम बल भागीदारी दर एवं बेरोजगारी दर का आकलन करना है। इसके माध्यम से रोजगार की वास्तविक स्थिति का व्यापक विश्लेषण संभव हो सकेगा, साथ ही संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार से होने वाली आय का भी निर्धारण किया जा सकेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक अर्थ एवं संख्या, सुशील कुमार ने किया। उन्होंने प्रशिक्षण की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि आंकड़ों का संकलन अत्यंत सावधानी और पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि राज्य की विकास योजनाओं के लिए विश्वसनीय आधार तैयार हो सके। इस अवसर पर अपर निदेशक पंकज नैथानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में संयुक्त निदेशक डॉ. दिनेश बडोनी एवं सुश्री चित्रा, डॉ. ईला पन्त बिष्ट, उप निदेशक निर्मल कुमार शाह एवं लालित मोहन जोशी, अर्थ एवं संख्याधिकारी अशोक कुमार तथा अपर सांख्यिकी अधिकारी नरेन्द्र सिंह सहित सभी जनपदों के अधिकारी और विकासखण्डों के सहायक संख्याधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार...

नर्सिंग बेरोजगारों के आंदोलन को उक्रांद का समर्थन

देहरादून संवाददाता. नर्सिंग भर्ती वर्षवार करने की मांग पर आंदोलन कर रहे नर्सिंग बेरोजगारों को उक्रांद ने गुरुवार को समर्थन दिया। एकता विहार में नर्सिंग एकता मंच का धरना गुरुवार को 56वें दिन भी जारी रहा। उक्रांद के सैनिक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष सूबेदार वीर सिंह पवार और केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी सहित अन्य नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर बेरोजगारों की समस्याएं सुनीं। नेताओं ने कहा कि 56 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के किसी प्रतिनिधि का आंदोलनकारियों से सुध न लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मूल निवासी युवाओं की जायज मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो नर्सिंग एकता मंच के साथ मिलकर प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कैप्टन खुशहाल सिंह गढ़िया, नवल पुंडीर, यश नेगी, प्रवेश रावत, शिरा बांधनी, उपेंद्र, पपेंद्र बिष्ट, हेमंत, नीमा और पवन सहित आदि मौजूद रहे।

अमर्यादित व्यवहार पर राष्ट्रपति को ज्ञापन

देहरादून संवाददाता. मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए कथित अमर्यादित व्यवहार के विरोध में भारतीय गौक्रान्ति मंच व गौसेवी संगठनों ने गुरुवार को जिलाधिकारीके माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। संगठनों ने निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग करते हुए दोषियों को दंडित करने की अपील की।

हरिद्वार में सड़क सुरक्षा का अभियान चलाया

हरिद्वार संवाददाता. 36वें सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को हरिद्वार में यातायात पुलिस और सीपीयू ने जनजागरूकता अभियान चलाया। बस अड्डा और रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख चौक-चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की, वहीं वाहन चालकों को नियमों के पालन का संदेश भी दिया गया। रोडवेज, टैक्सी यूनियन, आॅटो, विक्रम और ई-रिक्शा चालकों को विशेष रूप से जागरूक किया गया।

यूजीसी समता विनियम-2026 का एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन ने किया समर्थन

रुद्रपुर संवाददाता. अनुसूचित जातिख्रजनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अधिसूचित यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन संबंधी) विनियम-2026 का समर्थन करते हुए इसे सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। एसोसिएशन का कहना है कि ये विनियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर और गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होंगे। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हरिओम सिंह ने बताया कि इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लंबे समय से मौजूद जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना है, ताकि विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी भयमुक्त एवं सम्मानजनक माहौल में कार्य कर सकें। उन्होंने विशेष रूप से इस बात को रेखांकित किया कि पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी स्पष्ट कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। विनियमों के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र और समता समिति का गठन अनिवार्य किया गया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। इससे संस्थानों में सहभागिता आधारित और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हरिओम सिंह ने बताया कि संस्थान प्रमुख की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी, नियमित रिपोर्टिंग व्यवस्था और राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति जैसे प्रावधान इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं, गैर-अनुपालन की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि समता अब केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि अनिवार्य व्यवस्था है। एसोसिएशन ने यूजीसी के इस निर्णय की सराहना करते हुए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से विनियमों का ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ पालन करने की अपील की है।

रामनगर में एक सराहनीय पहल देखने को मिली

रामनगर संवाददाता. सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती हैइसी गंभीर सच्चाई को लोगों तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 के तहत रामनगर में एक सराहनीय पहल देखने को मिली।गुरुवार को श्री बाला जी मोटर्स शोरूम पर परिवहन विभाग द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के प्रति जागरूक करना था। यह अभियान केवल नियमों की याद दिलाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की सोच और आदत बदलने की कोशिश भी इसमें साफ दिखाई दी।कार्यक्रम के दौरान केवल जागरूकता ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कदम भी उठाए गए। बिना हेलमेट चल रहे कई दोपहिया वाहन चालकों के चालान किए गए और उन्हें निशुल्क हेलमेट वितरित किए गए।कई चालकों ने स्वीकार किया कि वे पहले हेलमेट को जरूरी नहीं समझते थे, लेकिन अब वे नियमित रूप से हेलमेट पहनने का संकल्प ले रहे हैं। यह पहल न केवल नियम पालन की ओर बढ़ाया गया कदम है, बल्कि जीवन सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक सोच भी है।

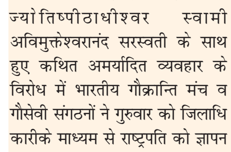

गर्मियों में वनाग्नि से निपटने को प्रशासन सतर्क, फायर सीजन को लेकर हुई तैयारियां

अल्मोड़ा संवाददाता. जनपद में आगामी गर्मी के मौसम के दौरान जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। फायर सीजन को देखते हुए अल्मोड़ा वन विभाग ने जिले भर में 147 क्रू स्टेशन स्थापित कर दिए हैं, जहां 550 फायर वाचरों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और फायर ब्रिगेड को भी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस वर्ष सर्दियों में अपेक्षित वर्षा नहीं होने के कारण कई क्षेत्रों में जंगल अपेक्षाकृत शुष्क बने हुए हैं और कुछ स्थानों पर आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सतर्कता बढ़ा दी है। अल्मोड़ा वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए विभागीय अमले के साथ ग्राम प्रहरी और युवक मंगल दलों का भी सहयोग लिया जाएगा,

जिससे समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। वनाग्नि से निपटने की रणनीति में इस बार आपदा मित्रों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में 184 आपदा मित्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिन्हें 11 तहसीलों में तैनात किया जाएगा। ये आपदा मित्र जंगलों पर नजर रखने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक भी करेंगे। ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी के कारण आग बुझाने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए इस बार प्राकृतिक जल स्रोतों के उपयोग की योजना बनाई गई है। वन विभाग को आवश्यकता पड़ने पर जल संस्थान की ओर से पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई जाएगी। सिविल सोयम वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप धौलाखंडी ने बताया कि फायर सीजन के मद्देनजर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और विभिन्न विभागों के समन्वय से वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयास किया जाएगा।

उद्यमियों को एफएसएसएआई पंजीकरण की दी गई जानकारी

अल्मोड़ा संवाददाता. ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना हवालबाग के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमियों को उद्यम स्थापना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में योजना से जुड़े उद्यमियों और सामुदायिक संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) विषय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें पंजीकरण की प्रक्रिया, आवश्यकता और लाभों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। सत्र में अभिहित अधिकारी अनिल मिश्रा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एफएसएसएआई पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन और विक्रय से जुड़े सभी उद्यमियों के लिए यह लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों, पंजीकरण की समयावधि तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्पाद को बाजार में उतारते समय उस पर एफएसएसएआई संख्या अंकित होना जरूरी है और पंजीकरण एक से पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। कार्यक्रम का शुभारंभ इन्क्यूबेशन मैनेजर अरुण अधिकारी ने किया। उन्होंने प्रशिक्षण सत्र की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उद्यमियों से योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रसार-प्रशिक्षण केंद्र हवालबाग से देवेंद्र साहू और ग्रामोत्थान से सुनील जोशी सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, योजना के लाभार्थी और स्टाफ मौजूद रहे। कुल 55 प्रतिभागियों ने सत्र में भाग लिया, जिनमें 30 प्रतिभागी ऑनलाइन तथा 25 प्रतिभागी ऑफलाइन माध्यम से जुड़े।

अल्मोड़ा की कथक नृत्यांगना डॉ. दीपा जोशी को डी.लिट्. की उपाधि

अल्मोड़ा संवाददाता. जिले की प्रख्यात कथक नृत्यांगना डॉ. दीपा जोशी को डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डी.लिट्.) की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है। वह उत्तराखंड की पहली तथा देश की दूसरी महिला कथक नृत्यांगना बन गई हैं, जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ है। यह उपाधि उन्हें खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित 17वें दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा द्वारा प्रदान की गई। डॉ. दीपा जोशी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों, विशेष रूप से गुरु प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णिमा पांडे तथा अपने माता-पिता को दिया है, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। वह दूरदर्शन की ए-ग्रेड कथक नृत्यांगना भी हैं और देश के विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर एकल प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। डॉ. जोशी की प्रारंभिक कथक शिक्षा अल्मोड़ा से शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, कथक केंद्र लखनऊ और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कथक की उन्नत शिक्षा के लिए उन्हें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति भी मिल चुकी है। नृत्य साधना के साथ-साथ उन्होंने संगीत विषय पर कई महत्वपूर्ण आलेख और पुस्तकें लिखकर शास्त्रीय कला के सैद्धांतिक पक्ष को भी समृद्ध किया है। वर्तमान में डॉ. दीपा जोशी देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संगीत संस्थानों और विश्वविद्यालयों में परीक्षक, चयन समितियों की सदस्य तथा विशेषज्ञ के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के नैनीताल कार्यालय में कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि से अल्मोड़ा में हर्ष का माहौल है।

बंदरों की समस्या पर शुरू हुआ अभियान, पार्षदों के संयुक्त प्रयास लाए रंग

अल्मोड़ा संवाददाता. नगर क्षेत्र में बंदरों की बढ़ती समस्या को लेकर पार्षदों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास और धरना कार्यक्रम का असर अब दिखाई देने लगा है। पार्षदों की मांग पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम में आयुक्त की नियुक्ति सुनिश्चित की और इसके साथ ही नगर क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इस पहल से शहरवासियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नगर हित से जुड़े इस मुद्दे को लेकर पार्षदों ने लगातार आवाज उठाई थी और बंदरों की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की थी। प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कदम उठाए जाने के बाद अब नगर निगम की ओर से अभियान शुरू होने से आम जनता में संतोष का माहौल देखा जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि वे नगर की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे और जनहित से जुड़े विषयों पर आगे भी एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे। बंदरों की समस्या को नियंत्रण में रखने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह अभियान नियमित रूप से प्रत्येक दो माह में चलाया जाएगा, ताकि स्थिति दोबारा गंभीर न हो सके। पार्षदों ने नगरवासियों से भी सहयोग की अपील करते हुए भरोसा

दिलाया कि शहर के विकास और जनसमस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। इस अवसर पर मेयर अजय वर्मा के साथ पार्षद प्रदीप चंद्र आर्य, कुलदीप मेर, वैभव पांडे, चंचल दुर्गापाल, मधु बिष्ट, गुंजन सिंह चम्याल, दीपक कुमार, रोहित कार्की, हेमचंद तिवारी, जानकी पांडे, अनूप भारती, नवीन चंद्र आर्य, राधा मटियानी, तुलसी देवी, मुकेश कुमार डैनी, भूपेंद्र जोशी, रीना टम्टा, इतिक्वाब आलम कुरैशी, गीता बिष्ट और कमला किरौला सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे।

मजदूर की मौत के मामले में बाइक सवार पर मुकदमा

रुद्रपुर संवाददाता. बाइक सवार की टक्कर से हुई मजदूर की मौत के मामले में भाई की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, वीरेश यादव पुत्र रवेन्द्र सिंह यादव निवासी नई बस्ती फुलसुंगा, मूल निवासी ग्राम बुरार्फरीदपुर जिला बदायूं यूपी ने बताया कि 23 जनवरी की रात साढ़े दस बजे उसका भाई सुदेश यादव दक्ष चौराहे से बगवाड़ा मार्ग पर पैदल जा रहा था। तभी तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। जिससे भाई की मौत हो गई। सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

लीडिगं कैडेट नंदनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलीं

रुद्रपुर संवाददाता. रिपब्लिक डे कैंप 2026 में प्रतिभाग कर रही सिटी कॉन्वेंट स्कूल की नेवी एनसीसी यूनिट की लीडिंग कैडेट नंदनी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने नंदनी को भविष्य में और अधिक अनुशासित, समर्पित एवं राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। विद्यालय प्रबंधन ने नंदनी एवं उनके परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। विद्यालय की नेवी एनसीसी यूनिट की एएनओ सब लेफ्टिनेंट वंदना जोशी ने कहा कि लीडिंग कैडेट नंदनी ने अपने कठोर परिश्रम, अनुशासन एवं नेतृत्व क्षमता के बल पर यह उपलब्धि प्राप्त की है। उनका आरडीसी 2026 में चयन और राष्ट्रपति से भेंट करना विद्यालय के लिए अत्यंत गर्व की बात है। यह अन्य कैडेट्स को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। विद्यालय के प्रबंधक प्रवीण उपाध्याय ने कहा कि कैडेट नंदनी की यह उपलब्धि विद्यालय, एनसीसी यूनिट एवं समस्त क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है।

समायोजित किए गए आठ शिक्षकों ने नहीं किया कार्यभार ग्रहण

रुद्रपुर संवाददाता. शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में समायोजित किए गए आठ सहायक अध्यापकों ने अब तक अपने नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। ऊधमसिंह नगर जिले में शिक्षा विभाग ने मानक से अधिक तैनात 22 सहायक अध्यापकों का रिक्त पदों पर समायोजन किया था। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) हरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या निर्धारित मानक से अधिक थी, जबकि कई स्कूलों में पद लंबे समय से खाली चल रहे थे। इसी असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से यह समायोजन किया गया।

आरपीएफ में नौकरी का झांसा देकर 6.35 लाख की ठगी

रुद्रपुर संवाददाता. रुद्रपुर निवासी युवक से उसके दो भाइयों को आरपीएफ में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6.35 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामेश्वर सिंह पुत्र प्रभु दयाल निवासी गणेश गार्डन फुलसुंगा रुद्रपुर ने ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन फरवरी 2025 को उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉलर ने अपना नाम नीरज यादव और खुद को एसटीएफ ऑफिसर बताया। उसने कहा कि उसका बड़ा भाई मनोज आरपीएफ दिल्ली में महानिदेशक है और अगर किसी को आरपीएफ में सरकारी पोस्ट पर नौकरी करनी हो तो उससे संपर्क करे। वह उसके झांसे में आ गया और अपने भाई पंकज दयाल व अमर की नौकरी लगवाने की बात कही। उसने व्हाट्सएप पर ही उसके भाइयों के सभी दस्तावेज ले लिए और रजिस्ट्रेशन हो जाने की बात कही। इसकी एवज में उसने 50 हजार की फीस देने को कहा। उसने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। आरोप है कि इसके बाद उसने उससे मामले की और जानकारी लेनी चाही तो उसने रजिस्ट्रेशन के नाम पर और रकम की डिमांड की। भाइयों की नौकरी के लिए करीब एक साल में अलग-अलग तारीखों पर छह लाख 35 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद भी उसके भाइयों की नौकरी नहीं लगी। बाद में उसे साइबर ठगी का अहसास हुआ।

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, अमीषा पटेल बोलीं- तारा सिंह को पर्दे पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं

सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म बॉर्डर-2 बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 1997 की क्लासिक ड्रामा फिल्म की सीक्वल फिल्म कमाई के साथ दर्शकों का भी दिल जीतने में पीछे नहीं हट रही है। आम जनता से लेकर मनोरंजन जगत तक हर कोई फिल्म की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। हाल ही में अभिनेत्री अमीषा पटेल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए फिल्म की तारीफ की। उन्होंने कहा, तारा सिंह को देखकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। मैं मानती हूं कि फिल्म में वरुण, दिलजीत और अहान समेत सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया होगा। मैं फिल्म और उसके गानों को फिर से महसूस करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। अमीषा पटेल ने फिल्म की तुलना पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक बॉर्डर 2 नहीं देखी है, लेकिन 1997 की बॉर्डर देखी है। फिर भी, जिस तरह लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लगता है कि टीम ने बहुत शानदार काम किया है। जैसे गदर 2 की तुलना गदर से की गई थी, लेकिन गदर 2 के हिट होने के बाद सबने माना था कि यह अलग और शानदार फिल्म है, इसलिए मुझे लगता है कि तुलना नहीं करनी चाहिए। ये गलत इंप्रेशन डालती है।

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म में नई कहानियों के साथ नए कलाकार भी शामिल हैं, जिनमें वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार सेना के जवानों के किरदार में नजर आ रहे हैं। वहीं, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेध ा राणा और अन्या सिंह जैसी अभिनेत्रियां हैं। यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के गाने दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। वे उन्हें नॉस्टेल्जिया का अनुभव करवा रहे हैं।बॉर्डर 2 के निर्माता गुलशन कुमार और टी-सीरीज हैं। फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह हैं, जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी. दत्ता, और निधि दत्ता इसके निर्माण में शामिल हैं। फिल्म को बिना किसी कट के यूए 13 प्लस के सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है।

एक्टिंग पहला प्यार तो खाना दूसरा, मास्टरशेफ में करिश्मा ने कपूर खानदान के खोले राज

कपूर खानदान अपनी पार्टियों और खाने-पीने के किस्सों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। अक्सर इस परिवार का कोई न कोई सदस्य मजेदार किस्से ताजा करता रहता है। अब खाने की बात चल रही है तो मास्टरशेफ इंडिया भी पीछे कैसे रह सकता है? कपूर परिवार की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर मास्टरशेफ इंडिया में स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आई। इस खास एपिसोड में करिश्मा ने बताया कि उनके परिवार में खाना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि प्यार, पुरानी यादों और परिवार के साथ बिताए पलों का प्रतीक रहा है। इस एपिसोड में कपूर खानदान की पसंदीदा क्लासिक इंडियन डिशेज को सेलिब्रेट किया गया। कंटेस्टेंट्स को चुनौती दी गई कि वे कपूर परिवार की विरासत वाली इन डिशेज की असली आत्मा को बनाए रखते हुए ओरिजिनल फ्लेवर के साथ मास्टरशेफ लेवल की क्रिएटिव डिश तैयार करें।वहीं, इसमें माहौल बनाते हुए शेफ रणवीर बरार कहते हैं, डिश की आत्मा, कपूर परिवार की विरासत, इन क्लासिक इंडियन डिशेज की ओरिजिनैलिटी को बचाते हुए एक मास्टरशेफ-लेवल की डिश बनानी है।करिश्मा ने सिनेमा और खाने के लिए अपने प्यार को भी दर्शाया। इसको लेकर अभिनेत्री ने कहा, एक्टिंग मेरा पहला प्यार है और दूसरा प्यार खाना है, क्योंकि यह बॉलीवुड के पॉपुलर कपूर खानदान की विरासत बांधते हुए आगे लेकर जा रही हैं।इसी के साथ ही करिश्मा ने इमोशनल कनेक्शन के बारे में बताया, हमारे परिवार का खाना हमेशा प्यार, यादों और साथ में रहा है। मास्टरशेफ इंडिया किचन के साथ खाने के लिए अपने परिवार के प्यार को शेयर करना मेरे लिए बहुत गर्व का पल था। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ये जोड़ियां देश के हर कोने से अपनी कहानियां और फ्लेवर लेकर आ रही हैं, जिससे यह शो गर्व का सच्चा सेलिब्रेशन बन गया है। वे मिलकर पूरे देश में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करती हैं।जब करिश्मा ने प्यार से बनी इन डिशेज का स्वाद चखा, तो उन्होंने कंटेस्टेंट्स की मेहनत और फ्लेवर की जमकर तारिफ की। भावुक होकर उन्होंने कहा, अगर राज कपूर, ऋषि, और रणबीर यहां होते, तो उन्हें भी बहुत पसंद आता।

धमाल 4 की रिलीज डेट में बदलाव, 12 जून नहीं अब इस दिन देगी सिनेमाघरों में दस्तक

मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल की चौथी किस्त धमाल 4 को लेकर दर्शकों में उत्सुकता चरम पर है। हालांकि, निर्देशक इंद्र कुमार की इस फिल्म की रिलीज डेट में एक बार फिर बदलाव हुआ है। मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की कि फिल्म अब 12 जून को रिलीज नहीं होगी। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब अराजकता कॉमेडी से मिलती है, तो समझ लीजिए कि यह धमाल का समय है! नई तारीख शुभ और फैमिली एंटरटेनर के लिए बेस्ट है। 3 जुलाई को फिल्म अल्टीमेट फैमिली एंटरटेनर के रूप में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। यह रिलीज डेट में दूसरी बार बदलाव है। इससे पहले फिल्म 12 जून को रिलीज होने वाली थी और उससे पहले ईद के मौके पर आने वाली थी। मेकर्स ने कुछ वजहों से तारीख बदली, हालांकि वजहों का खुलासा नहीं किया गया। माना जा रहा है कि संभावित बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है।धमाल 4 में अजय देवगन लीड रोल में हैं। उनके साथ संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पटकर और रवि किशन जैसे शानदार एक्टर्स अहम किरदार में नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी के पराने सितारे जैसे रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी इसमें शामिल हैं।फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है। इसे टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स में अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक शामिल हैं।धमाल फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2007 में हुई थी, जिसमें संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी मुख्य भूमिका में थे। इंद्र कुमार ने ही इसे डायरेक्ट किया था। इसके बाद साल 2011 में डबल धमाल और 2019 में टोटल धमाल रिलीज हुई, जो हिट साबित हुई। धमाल 4 इस सीरीज की नई किस्त है, जो पुरानी मस्ती और नए ट्विस्ट के साथ दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर जल्द रिलीज होने की उम्मीद है।

बॉर्डर 2 में जैकी श्रॉफ और तब्बू को क्यों नहीं मिली जगह, डायरेक्टर अनुराग सिंह ने तोड़ी चुप्पी

फिल्मों के सीक्वल को लेकर दर्शकों की उम्मीदें हमेशा बहुत ज्यादा होती हैं। खासकर जब बात 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर की हो, तो सनी देओल, जैकी श्रॉफ और तब्बू जैसे कलाकारों ने उस फिल्म को खास बनाया था, लेकिन बॉर्डर 2 में जैकी श्रॉफ और तब्बू की कमी दर्शकों ने महसूस की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए दोनों को फिल्म में शामिल न करने को लेकर कई सवाल किए।

अब इन सभी सवालों का जवाब फिल्म निर्देशक अनुराग सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए दिया। बॉर्डर 2 के निर्देशक अनुराग सिंह ने कहा, किसी भी फिल्म की कास्टिंग भावनाओं या पुराने जुड़ाव के आधार पर नहीं, बल्कि कहानी की जरूरत के अनुसार होती है। फिल्म बनाते वक्त सबसे पहले कहानी पर ध्यान दिया जाता है, न कि इस बात पर कि किस अभिनेता को दोबारा लिया जाए। कहानी जिस तरह के किरदार मांगती है, कलाकारों का चयन उसी हिसाब से किया जाता है। अनुराग सिंह ने कहा, कोई भी निर्देशक यह सोचकर स्क्रिप्ट नहीं लिखता कि उसे किसी खास अभिनेता को ही लेना है। पहले एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जो सच्ची लगे और दिल को छुए। उसके बाद यह सोचा जाता है कि उस किरदार को कौन सा कलाकार अच्छे से निभा पाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किरदार लिखते समय किसी अभिनेता का चेहरा अपने आप दिमाग में आ जाता है, लेकिन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, दबाव में लिया गया फैसला नहीं है।सनी देओल को लेकर अनुराग सिंह ने कहा, बॉर्डर फ्रेंचाइजी को अगर किसी चेहरे से सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, तो वह सनी देओल हैं। बॉर्डर नाम आते ही दर्शकों के मन में सनी देओल की छवि उभर आती है। इसलिए अगर बॉर्डर बनाई जा रही है, तो उसमें सनी देओल का होना जरूरी है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सनी देओल और निर्देशक जेपी दत्ता की पहचान बन चुकी है।अनुराग सिंह ने कहा, रचनात्मकता पर जोर डालकर किसी अभिनेता को कहानी में फिट नहीं किया जा सकता। कुछ फिल्मों में यह संभव हो सकता है, लेकिन बॉर्डर 2 जैसी गंभीर और भावनात्मक फिल्म में ऐसा करना सही नहीं होता। अगर कहानी किसी और दिशा में जा रही है, तो कलाकारों का चयन भी उसी रास्ते पर चलता।निर्देशक ने कहा, पूरी स्क्रिप्ट, किरदारों की गहराई और कहानी की मांग को देखकर मुझे लगा कि जो कास्ट चुनी गई है, वही इस फिल्म के लिए सबसे सही है। इसलिए उसी फैसले के साथ आगे बढ़ा गया। किसी कलाकार को शामिल न करने का मतलब यह नहीं कि उनके काम या योगदान को कम आंका गया है।बॉर्डर 2 में इस बार नई पीढ़ी के कलाकारों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार सेना के जवानों के किरदार में नजर आ रहे हैं।

हिन्दी दैनिक जोखिम

सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की एविएशन क्षेत्र में देशभर में बनी नई पहचान

: विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को बड़ी सफलता, एविएशन इकोसिस्टम में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार

: एविएशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित

देहरादून संवाददाता. हैदराबाद स्थित बेगमपेट एयरपोर्ट में 29ख31 जनवरी 2026 को आयोजित देश के प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट "विंग्स इंडिया 2026" में उत्तराखंड राज्य को "एविएशन और इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा राज्य" के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की प्रभावी एविएशन नीतियों का परिणाम है। यह सम्मान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव आशीष चौहान एवं संजय टोलिया सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ-साथ चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने में एविएशन सेक्टर का प्रभावी उपयोग किया है। केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के लिए हेली सेवाओं का विस्तार, हेलीपोर्ट और हेलीपैड का विकास, यात्रियों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन सेवाओं में हवाई संसाधनों का बेहतर

उपयोग उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान बना है। चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों और समय की कमी से जूझ रहे श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसकी देश-भर में सराहना हुई। इसके साथ ही सीमांत और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने, उड़ान योजना, एयर स्ट्रिप्स के उन्नयन और हेली-टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी राष्ट्रीय मंच पर विशेष रूप से सराहा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड की जनता, राज्य सरकार की टीम और एविएशन सेक्टर से जुड़े सभी हितधारकों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में चारधाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल एवं तकनीक-समर्थ बनाने के साथ-साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी एविएशन और हेली-टूरिज्म हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मान उत्तराखंड के लिए पर्यटन, निवेश, रोजगार और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगा।

यह पुरस्कार उत्तराखंड की समग्र विमानन नीति, बेहतर प्रशासनिक समन्वय और प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ना हमारी प्राथमिकता रही है, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिला है बल्कि आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से ली सेवाओं के विस्तार, उड़ान योजना के सफल क्रियान्वयन और आधुनिक विमानन अवसंरचना के विकास से उत्तराखंड तेजी से एक उभरते विमानन हब के रूप में स्थापित हो रहा है। : पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

राष्ट्रपति निकेतन में गूंजा 'सुरक्षित जीवन' का मंत्र

देहरादून संवाददाता. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को राष्ट्रपति निकेतन के ऐतिहासिक परिसर में परिवहन विभाग की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता कर यातायात नियमों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सालावाला के छात्रों ने भावनात्मक नुक्कड़ नाटक के जरिए नियमों की अनदेखी के घातक परिणामों को दर्शाया। साथ ही रोड सेफ्टी क्विज और पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग और गुड समैरिटन कानून की विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि दुर्घटना में घायल की मदद करने वाला व्यक्ति समाज का नायक है, जिसे कानून पूरी सुरक्षा देता है। संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा और राष्ट्रपति निकेतन की प्रबंधक एकता उनियाल ने बच्चों को अनुशासित नागरिक बनने की प्रेरणा दी। आरटीओ डॉ. अनीता चमोला ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं, बल्कि एक जीवन मूल्य है। आज बच्चों में बोए गए ये संस्कार कल एक सुरक्षित समाज की नींव रखेंगे। विरासत के साथ जागरूकता कार्यक्रम के अंत में बच्चों को राष्ट्रपति निकेतन का भ्रमण कराया गया, जिससे उन्हें राष्ट्रीय धरोहर और पर्यावरण संरक्षण की सीख मिली। इस दौरान एआरटीओ अनिल नेगी, श्वेता रौथाण और प्रवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे। आरटीओ प्रशासनने बेहतरीन समन्वय के लिए राष्ट्रपति निकेतन प्रबंधन का आभार व्यक्त किया।

संक्षिप्त समाचार...

मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने बचाई स्कूल टीचर की जान

देहरादून संवाददाता. मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल और दुर्लभ सर्जरी कर महिला की जान बचाई। रुड़की की 45 वर्षीय स्कूल टीचर पूनम हरिद्वार के पास एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थीं। जब बाइक के पहिये में दुपट्टा फंसने से उनकी गर्दन की सांस की नली (विंडपाइप) लगभग पूरी तरह फट गई थी। पति संदीप कुमार के साथ तीन जनवरी को वह सुबह एक कार्यक्रम में जा रहे थे। हादसे के बाद मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी और हवा उनकी त्वचा व सीने में भर गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉ. अरविंद मक्कर (डायरेक्टर - कार्डियक, थोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी) और डॉ. इरम खान (सीनियर कंसल्टेंट - ईएनटी) की नेतृत्व वाली टीम ने तुरंत इमरजेंसी सर्जरी का फैसला लिया। डॉ. अरविंद मक्कर और डॉ इरम ने ने बताया कि विंडपाइप का इस तरह फटना एक दुर्लभ और जानलेवा चोट है। सर्जरी के बाद गले में सूजन को संभालने और सुरक्षित रिकवरी के लिए डॉक्टरों ने एक अस्थायी श्ट्रेकियोस्टोमीश (सांस के लिए बाईपास) भी की। समय पर सही निर्णय और एडवांस इलाज के चलते पूनम अब खतरे से बाहर हैं और सामान्य जीवन की ओर लौट रही हैं।

फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना दंपति को भेजे अश्लील मैसेज

देहरादून संवाददाता. इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर महिला और उसके पति को अश्लील मैसेज भेजे गए। आरोप है कि विरोध करने पर धमकियां दी गई। महिला की शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को सहारनपुर जिले के दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि निरंजनपुर मंडी क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते छह जनवरी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पति के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई। इस आईडी के जरिए दंपति को लगातार अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। फर्जी एकाउंट से सोशल मीडिया पर उनके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और पति के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की नीयत से प्रचार भी किया। पीड़िता का आरोप है कि आईडी ब्लॉक कराने पर आरोपी नए तरीकों से संपर्क कर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। शिकायत में नवनीत सिंह परूथी निवासी सहारनपुर नुमाईश कैंप निकट भारतमाता चौक और पुनीत निवासी पुष्पांजली विहार जनता रोड निकट गोल्ड स्टोर सहारनपुर पर आरोप हैं। इंस्पेक्टर अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों पर आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

दून में आज अध्यात्मिक सत्संग करेंगे संत सुधांशु महाराज

देहरादून संवाददाता. विश्व जागृति मिशन के संत सुधांशु महाराज के शुक्रवार की सायं 4 से 6 बजे तक चौधरी फार्म हाउस जनरल महादेव सिंह रोड में एक दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग में प्रवचन देंगे। गुरुवार को निर्विघ्न आयोजन के लिए मिशन के पदाधिकारियों ने सत्संग स्थल पर हवन एवं पूजन किया। मिशन के आचार्य महेश शर्मा एवं आचार्य कुलदीप पांडेय के सानिध्य में हवन पूजन में काफी संख्या में श्रद्धालु जुटे। विश्व जागृति मिशन के प्रचार मंत्री भूपेन्द्र चड्ढा ने बताया कि भक्तों के बैठने के लिए चौधरी फार्म हाउस में कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई है स पंडाल को भव्य रूप से सजाया जा रहा है स सुधांशु महाराज शुक्रवार की सुबह नौ बजे जॉलीग्रांट एयर पोर्ट पहुंचेंगे। वहां से अपर तुनवाला आनंद देव लोक आश्रम में आएंगे, कुछ देर वहां ठहरने के पश्चात बद्रीपुर होते हुए मिशन के प्रधान सुधीर शर्मा के केशव विहार जीएम एस रोड स्थित आवास पर पहुंचने पर अनुयायियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।

पीएम मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन को जमीन पर उतारने में हडको बनेगा उत्तराखंड का मजबूत साझेदार

देहरादून संवाददाता. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को सुनियोजित, आधुनिक एवं समावेशी राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। राज्य में सभी के लिए आवास, नए नगरों के विकास और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विस्तार को गति देने के उद्देश्य से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) के सहयोग से संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना एवं भविष्य की शहरी विकास रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक का मुख्य फोकस राज्य में आवासीय जरूरतों को दीर्घकालिक दृष्टि से पूरा करना, विशेषकर ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और एलआईजी (निम्न आय वर्ग) के लिए सस्ते, सुरक्षित और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराना रहा।2047 और 2050 तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर रणनीति: बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2047 के विकसित भारत लक्ष्य और 2050 तक की आवासीय जरूरतों के लिए एक समग्र एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाए। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुनियोजित निर्माण, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और भविष्य के नए नगरों की परिकल्पना शामिल होगी।नए नगरों के विकास में हडको देगा पूर्ण सहयोग: हडको के क्षेत्रीय प्रमुख एवं राज्य प्रभारी संजय भार्गव ने राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड में नए शहरों और टाउनशिप के विकास, भूमि अधिग्रहण, मास्टर प्लानिंग और वित्तीय सहयोग में हडको अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का पूरा लाभ राज्य को देगा। देश के विभिन्न राज्यों में नए नगर बसाने के अनुभव को उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा।शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास: बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि आवासीय योजनाएं केवल शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनियोजित ढंग से लागू हों।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक संजीव पंत द्वारा जेल रोड, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं चिराग पब्लिकेशन जेल रोड, हल्द्वानी नैनीताल से मुद्रित। सम्पादक - राजेश पंत
फोन नं0- 05946-254443 प्रसार प्रबंधकः वसीम अहमद , आर एन आई नं.: UTTHIN/2010/36647 email: jokhimhaldwani2013@gmail.com
ताज़ातरीन खबरों व सही जानकारी के साथ समाचार को विस्तार से पढ़ने के लिए लागआन करें हमारा newsportal:. jokhimnews.com